

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी:- ओम कशोरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या -150/2015 (अपील)

1. राधेश्याम आत्मज श्री भेरु जाति तेली निवासी ग्राम मोडक तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलाण्ट.

वनाग

1. मंगलम सीमेन्ट लि0 आदित्य नगर मोडक, तहसील रामगंजमण्डी जरिये मैनेजर एवं अधिकृत अधिकारी आदित्य नगर मोडक, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

---रेस्पोंडेन्ट.

अपील अण्डर सेक्शन 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्ध नामातकरण संख्या 439 तहसीलदार रामगंजमण्डी दिनांक 31.10.2012

उस्थिति

1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक अपीलांत

निर्णय

दिनांक- 26.02.2020

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रामगंजमण्डी द्वारा नामा0 सं0 439 ग्राम मोडक में दिनांक 31.10.2012 को आदेश पारित किया कि-“ नामा0 पेश हुआ रिपोर्ट पटवारी पटवारी व जांच आई.एल.आर के आधार पर व अधिसूचना दिनांक 2.6.80, श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (भू.आ.अ.) कोटा के आदेश क्रमांक/केश/2012/202 दिनांक 3.10.2012, श्रीमान तहसीलदार सा0 रामगंजमण्डी के आदेश क्रमांक/भू.अ./2012/3226 दिनांक 5.10.2012 की पालना में ख.नं 1776/0.40, 1766/0.42, 1774/2.43, 1769/1.62, 1765/0.52 1770/1.13 मंगलम सीमेंट लि0 मोडक (माइनिंग कार्य हेतु) दर्ज करना स्वीकार है, रिकार्ड में अमल हो ।” बाबत आदेश पारित किया ।
3. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 08.05.2015 को लिमिटेड एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का मौका प्रदान किये बिना कब्जा व मौका स्थिति व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही आदेश जैर अपील प्रदान किया है जो कि हर प्रकार से काविल निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 2.6.1980 की पालना में दिनांक 31.10.2012 को नामान्तकरण खोला है जबकि उक्त आदेश की पालना रेस्पोंड द्वारा नहीं की गई ना ही अपीलान्त को व पूर्व खतेदार को कोई मुआवजा ही दिया गया है । रेस्पोंड द्वारा गुप चुप तरीके से सन 80 के आदेश की पालना



Om

में 30 साल बाद नामान्तकरण तस्दीक करवाया है जो किसी प्रकार से नहीं खोला जा सकता है । विवादित आराजी पर काश्तकारी होती है तथा सं0 2067-2070 की जमाबंदी में खातेदारान का नाम अंकित है बिना कब्जे के संबंध में तथा जिस आदेश की पालना में नामान्तकरण तस्दीक किया गया है उक्त आदेश की रेस्प0 के द्वारा पालना की गई या नहीं की गई जांच किये बिना ही नामान्तकरण तस्दीक किया गया है । विवादित आराजी पर किसी प्रकार से रेस्प0 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ना ही उनका कब्जा है इसके उपरान्त भी आदेश जैर अपील प्रदान किया गया है जो कि हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है । आदेश जैर अपील अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही खोला गया है अपीलान्ट को आदेश जैर अपील की सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 29.7.2015 को अपीलान्ट के कब्जे में जबरन रेस्प0 के प्रतिनिधियों के द्वारा दखलन्दाजी करने पर तथा उक्त आराजी रेस्प0 के नाम खाते में दर्ज होने की बात कहने पर हुई उक्त प्रकार जानकारी होने पर दिनांक 30.7.2015 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 4.8.2015 को नकल मिली, नकल प्राप्त करके अपीलान्ट अपील खर्चे का इन्तेजाम करने गांव गया तो बीमार हो गया तथा टाईफाईड हो गया जिसका उसने देशी इलाज करवाया, अपीलान्ट की तबीयत में सुधार होने पर वह दिनांक 4.9.2015 को वकील साहब से मिला तथा अपील तैयार करवाकर यह अपील पेश कर रहा है जो सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 29.7.2015 से नकल प्राप्ति के दिन तथा बीमारी के दिन 4.9.2015 तक के दिन मुजरा करने पर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जैर अपील निरस्त किया जावे तथा रेस्प0 के पक्ष में तस्दीक किया गया नामान्तकरण निरस्त किया जावे ।

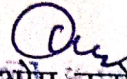
अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प0 को तलब किया गया । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 2.6.1980 की पालना में दिनांक 31.10.2012 को नामान्तकरण खोला है जबकि उक्त आदेश की पालना रेस्प0 द्वारा नहीं की गई ना ही अपीलान्ट को व पूर्व खतेदार को कोई मुआवजा ही दिया गया है । रेस्प0 द्वारा गुप चुप तरीके से सन 80 के आदेश की पालना में 30 साल बाद नामान्तकरण तस्दीक करवाया है जो किसी प्रकार से नहीं खोला जा सकता है । विवादित आराजी पर काश्तकारी होती है तथा सं0 2067-2070 की जमाबंदी में खातेदारान का नाम अंकित है बिना कब्जे के संबंध में तथा जिस आदेश की पालना में नामान्तकरण तस्दीक किया गया है उक्त आदेश की रेस्प0 के द्वारा पालना की गई या नहीं की गई जांच किये बिना ही नामान्तकरण तस्दीक किया गया है । विवादित आराजी पर किसी प्रकार से रेस्प0 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ना ही उनका कब्जा है इसके उपरान्त भी आदेश जैर अपील प्रदान किया गया है जो कि हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है ।

Om



6. वकील रेस्पोजेन्ट द्वारा कथन किया गया है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार भूमि अवाप्ति के कार्यवाही की गई है । सरकार के निर्देशों के क्रम में ही तहसीलदार नायब तहसीलदार चेचट द्वारा मंगलम सीमेंट लि० मोडक के माईनिंग कार्य हेतु दर्ज कर स्वीकार किया गया है, इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है । मंगलम सीमेंट द्वारा अपीलांट को नियमानुसार मुआवजा भुगतान किया गया है । रेस्पोजेन्ट अवाप्ति भूमि ख.नं 1776/0.40, 1766/0.42, 1774/2.43, 1769/1.62, 1765/0.52 1770/1.13 पर खनिज कार्य हेतु मंगलम सीमेंट लि० मोडक के नाम दर्ज की गई है, जैर अपील नामा० में कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।
7. हमने अपीलांट की बहस सुनी, व बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । यह अपील नायब तहसीलदार चेचट के नामा० सं० 439 आदेश दिनांक 31.10.2012 के विरुद्ध लिमिटेड एक्ट के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 8.9.2015 को पेश की गई है । उक्त अपील विलम्ब से पेश की गई है किन्तु विलम्ब के लिए बताए गये कारण जानकारी का अभाव व बिमारी के कारण विलम्ब होना बताया गया , न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए लिमिटेड का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को मुजरा करते हुए अपील अवधि मध्य मानी जाती है ।
8. पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 2.6.1980 के अनुसरण में भूमि अवाप्ति अधिकारी परियोजना कोटा द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी के आदेश की अनुपालना में नायब तहसीलदार चेचट द्वारा जैर अपील नामा० सं० 439 आदेश दिनांक 31.10.2012 स्वीकृत किया गया है, जिसमें उक्त भूमि ख.नं 1776/0.40, 1766/0.42, 1774/2.43, 1769/1.62, 1765/0.52 1770/1.13 हे. मंगलम सीमेंट लि० मोडक के नाम माईनिंग कार्य हेतु दर्ज की गई है । चूंकि जमाबंदी में खनन कार्य का ही नोट लगा रहेगा जिसमें भूमि मूल खातेदार के नाम ही रहेगी , इसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते है ।
9. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के नामा० सं० 439 दिनांक 31.10.2012 में हम कोई त्रुटि नहीं पाते है तथा जैर अपील आदेश यथावत रखा जाता है ।
10. निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


 ज(ओम कसरा)
 जिला कलेक्टर कोटा